महाराष्ट्र में भी शुगर मिलों से होगा टकराव

मिलों का डर: इंडस्ट्री के मुताबिक, राज्य में विधानसभा चुनाव पास होने से किसान संगठन गन्ने की कीमत का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे

[जयश्री भोसले | पुणे]

उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी किसान संगठन और चीनी मिलों के टकराने की स्थिति बन रही है। देश में सबसे अधिक चीनी का प्रॉडक्शन करने वाले महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई का नया सीजन एक महीने से भी कम समय में शुरू होने वाला है। राज्य विधानसभा के चुनाव नज़दीक होने की वजह से शुगर इंडस्ट्री का मानना है कि किसान संगठन गन्ने की कीमत के मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि, राज्य सरकार ने गन्ने का दाम तय करने के लिए शुगरकेन बोर्ड के गठन में देरी की है।

स्वाभिमानी शेतकारी संगठन (एसएसएस) के नेता और सांसद राजू शेट्टी ने कहा, 'पहले बोर्ड बनने दीजिए। हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है।' राज्य की शुगर इंडस्ट्री को गन्ने के दाम को लेकर विवाद होने की उम्मीद है। लेकिन यह स्पष्ट है कि वह फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस (एफआरपी) से ऊंची कीमत देने में सक्षम होगी। कोल्हापुर की वर्ना शुगर को-ऑपरेटिव के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर वी एस चव्हाण ने कहा, 'चीनी की मौजूदा कीमतों पर मिलों के लिए एफआरपी को भी देना मुश्किल होगा।'

- **महाराष्ट्र में गन्ने** की पेराई का नया सीजन एक महीने से भी कम समय में शुरू होने वाला है
- **चीनी** का एक्स-मिल शुगर प्राइस महाराष्ट्र में 28.50 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले वर्ष के समान है
- **राज्य सरकार** ने भी गन्ने का दाम तय करने के लिए शुगरकेन बोर्ड के गठन में देरी की है

महाराष्ट्र में चीनी का एक्स-मिल शुगर प्राइस 28.50 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले वर्ष के समान है। कोल्हापुर में एक अन्य शुगर को-ऑपरेटिव के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया, 'हम केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज लोन की वजह से पिछले वर्ष एफआरपी दे सके थे।

इस वर्ष एफआरपी में 100 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी और मिलों को कोई लोन न मिलने की संभावना को मानते हुए एफआरपी देना एक बड़ी चुनौती होगी।'महाराष्ट्र के को-ऑपरेशन मिनिस्टर हर्षवर्धन पाटिल ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार स्टैटुअरी शुगरकेन प्राइस कंट्रोल बोर्ड बनाएगी जो 2014-15 के पेराई सीजन के लिए गन्ने की कीमत तय करेगा। हालांकि, इस मोर्चे पर कोई प्रगति नहीं होने की वजह से इंडस्ट्री को लगता है कि मौजूदा सरकार गन्ने की कीमत का मुद्दा अगली सरकार के लिए गर्म रखना चाहती है। महाराष्ट्र के को-ऑपरेशन सेक्रेटरी राजगोपाल देवारा ने बताया, 'हम शुगरकेन प्राइस बोर्ड में नॉन-ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट कर रहे हैं।' सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अगर चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाती है तो भी बोर्ड गन्ने की कीमत की घोषणा कर सकता है।

अगर महाराष्ट्र में बोर्ड बनाया जाता है तो वह गन्ने की कीमत की पहली किस्त के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए एफआरपी को घोषित कर सकता है। शुगरकेन प्राइस एक्ट के मुताबिक, बोर्ड को तीन मीटिंग करनी होंगी। एक गन्ने की पहली किस्त पर फैसले के लिए पेराई सीजन शुरू होने से पहले, दूसरी पेराई सीजन के मध्य में और तीसरी गन्ने की अंतिम कीमत तय करने के लिए पेराई सीजन के अंत में की जाएगी।

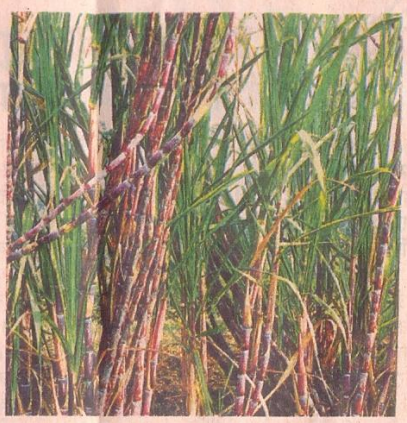

> "महाराष्ट्र की सरकार शुगरकेन प्राइस कंट्रोल बोर्ड बनाएगी जो 2014-15 के पेराई सीजन के लिए गन्ने की कीमत तय करेगा
>
> **हर्षवर्धन पाटिल,** को-ऑपरेशन मिनिस्टर, महाराष्ट्र